

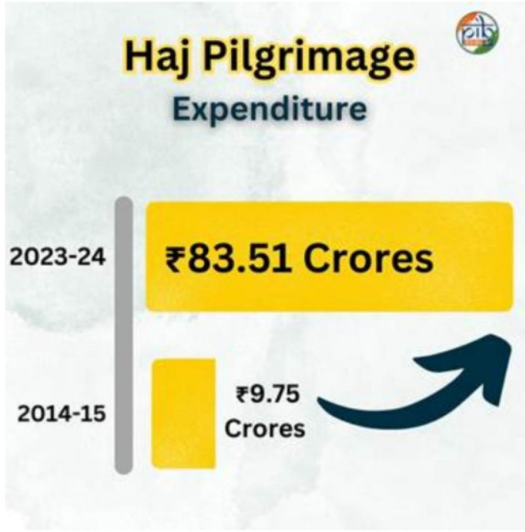
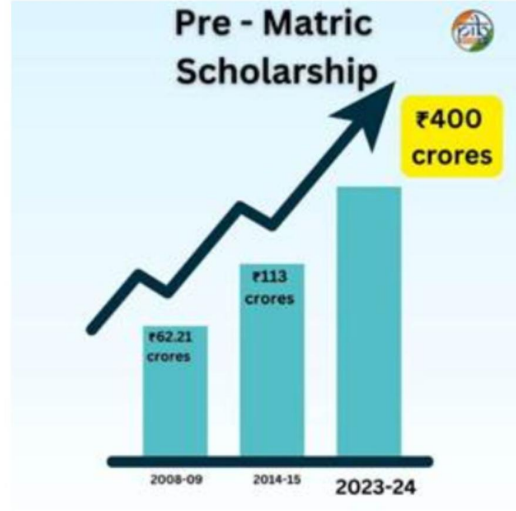
## अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तीकरण

**स्रोत: पी.आई.बी.**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने [अल्पसंख्यक समुदायों](#) को सशक्त बनाने के लिये भारत में जारी पर्यासों पर प्रकाश डाला।

### अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियोजना (2007):** इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा और रोज़गार क्षमता वर्द्धन हेतु [छात्रवृत्ति](#) प्रदान की जाती है।
  - इस योजना के तहत धन का आवंटन वर्ष 2008-09 में 70.63 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 बढ़कर 1000 करोड़ रुपए हो गया।
- **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियोजना (2008):** इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है तथा स्कूली शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - वर्ष 2008-09 में इस योजना हेतु 62.21 करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे जसिे वर्ष 2023-24 में बढ़कर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त नगिम (NMDFC) (1994):** यह अल्पसंख्यकों के पछिड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये स्वरोज़गार और आय-सृजन गतिविधियों के लिये रियायती ऋण प्रदान करता है।
  - वर्ष 2014-15 इसका आवंटन 2 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- **हज तीर्थयात्रा सहायता (2016):** इसके अंतर्गत नमिन आय वाले व्यक्तियों के लिये [हज तीर्थयात्रा](#) (सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का तक) की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - इसका व्यय वर्ष 2014-15 में 9.75 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 83.51 करोड़ रुपए हो गया।
- **जियो पारसी योजना (2013):** इसका उद्देश्य वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से [पारसी](#) समुदाय के लोगों की संख्या में होने वाली नरितर कमी की रोकथाम करना है।
  - मार्च 2024 तक, इस योजना के तहत 400 से अधिक पारसी बच्चों के जन्म को सक्षम बनाया गया है, जसिके लिये वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- **प्रधानमंत्री वरिसत का संबर्द्धन (PM VIKAS):** [PM VIKAS](#) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पाँच मौजूदा योजनाओं जैसे [USTTAD \(विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण\)](#), [नई मंजलि](#), [नई रोशनी](#) और [हमारी धरोहर](#) को मलिकर कौशल विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यकों को सशक्त बना रहा है।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK):** [PMJVK](#) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जसिमें स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला परियोजनाएँ, जलापूर्ति, स्वच्छता और खेल शामिल हैं।



## भारत के अल्पसंख्यक समुदाय

- **अल्पसंख्यक समुदाय:** केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCMA), 1992 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित करती है, जिसके तहत मुसलमानों, सखियों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों (वर्ष 2014 में जोड़े गए) और जोरास्ट्रियन (पारसी) को आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता दी जाती है।
  - कुल मिलाकर वे भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% हिस्सा हैं ([जनगणना 2011](#))।
  - जबकि अधिकांश राज्य केंद्रीय सूची का पालन करते हैं, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की अपनी सूची हो सकती है (उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में यहूदी एक अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं)।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - [अनुच्छेद 29](#) अल्पसंख्यकों के अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकारों की रक्षा करता है तथा धर्म, नस्ल, जातीय भाषा के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
  - [अनुच्छेद 30](#) अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिये संस्थाएँ:**
  - **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय:** वर्ष 2006 में स्थापित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग होकर, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रमों का समन्वय करता है।
  - **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM):** NCMA 1992 के तहत निर्मित [NCM](#) संविधान और संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुरूप अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करता है।
  - **वक्फ अधिनियम, 1995:** [वक्फ संपत्तियों](#) के प्रबंधन और विकास को नियंत्रित करता है।
    - **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों को सहयोग देते हुए वक्फ संपत्तियों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में, यदकिसी धार्मकि संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह कसि वशिष लाभ का हकदार है? (2011)

1. वह वशिष शैक्षणकि संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है।
2. भारत का राष्ट्रपतिसमुदाय के एक प्रतनिधि को स्वचालति रूप से लोकसभा में नामति करता है।
3. वह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है।

उपरयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्तमान में मुसलमानों, सखिों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और पारसियों (पारसी) को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धार्मकि समुदायों के रूप में अधसूचति कया गया है। ऐसे कुछ वशिष लाभ हैं जनिके कारण ये सभी समुदाय भारत के संवधान के साथ-साथ वभिन्न अन्य वधायी और प्रशासनकि उपायों के तहत हकदार हैं।
- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 30 धार्मकि एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणकि संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार को बरकरार रखता है। अतः कथन 1 सही है। भारत के राष्ट्रपतिके लयि कसि अल्पसंख्यक धार्मकि समुदाय के सदस्य को लोकसभा के लयि स्वचालति रूप से नामति करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान पहले ँग्लो-ईडयिन समुदाय के सदस्यों के लयि संवधान के अनुच्छेद 331 के तहत उपलब्ध था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- धार्मकि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम शकिषा, कौशल वकिस, रोजगार और सांप्रदायकि संघर्षों की रोकथाम के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनशिचति करने हेतु वर्ष 2005 में शुरू कया गया था। अतः कथन 3 सही है। अतः वकिलप (C) सही उत्तर है।